



102
07/12/07

64

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

W.P. (S) No. 7088 of 2007

PETITIONER

C.K. Jaiswal, aged about 50 years, s/o Shri Bharat Lal Jaiswal, by post Sub Engineer (under Suspension) in the Office of Executive Engineer, Hasdev Barrage Water Management Division at Rampur, Korba (C.G) - at present attached to the Office of Chief Engineer, Hasdev Basin water Resources department, Bilaspur, Distt. Bilaspur (C.G).

Versus

RESPONDENTS

- 1 State of Chhattisgarh, Through the Secretary, Department of Water Resources, D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur (C.G.)
- 2 Engineer in Chief, Department of Water Resources, Raipur, Distt. Raipur (C.G).
3. Chief Engineer, Water Resources Department, Hasdev Basin (Kachhar), Bilaspur, Distt. Bilaspur (C.G).
4. The Executive Engineer, Water Resources Department, Hasdev Barrage, water Management Divn., at Rampur, Korba, Distt. Korba (C.G).

**WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

Appearance:

Shri J.A. Lohani, Counsel for the petitioner.

Shri A.S. Kachhawaha, Govt. Advocate, for the State/ respondents on advance copy.

ORAL ORDER

(29.11.2007)

SUNIL KUMAR SINHA, J

Heard on admission.

The petitioner, who is Sub-Engineer and in-charge of Sub-Divisional Officer (under suspension), has challenged the charge sheet dated 05.11.2007 issued to him by the competent authority. He has also challenged the validity of the suspension order dated 14.08.2007 (Annexure P-1). The charges levelled against the petitioner are as under:

आरोप कं.1

- 1-0 आपने जुलाई 06 से मई 07 के मध्य स्वयं ने तथा अपने उप अभियंताओं से ऐसे संस्करण एवं रखरखाव के कार्य, जो कार्य विभाग नियमावलि भाग एक के नियम 2.075 (बी) के तहत विविध आमंत्रित कर ठेकों पर करण जना आवश्यक थे, को निविदा आमंत्रित कर ठेकों पर करण जना आवश्यक थे, को निविदा दायों के अनुसार कम दायों पर कार्य करा कर लाखों रुपये की बचत की जा सकती थी। इस प्रकार आपने अनियमित पद्धति से कार्य करण करण को वित्तीय हानि पहुँचाई है, जिसका विस्तृत चलेख अभिकथन पत्र में किया गया है।
- 1-1 बैरज के डूबान क्षेत्र में से फलाई एश हटाने के लिए रु. 28.30 लाख की तकनीकी स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/2700 आयोजनोत्तर के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता से प्राप्त की। इसके अतिरिक्त आपने पूर्व में स्वीकृत तकनीकी स्वीकृति की राशि का पूर्ण उपयोग किए बिना इसी कार्य हेतु 29.50 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजनोत्तर के अंतर्गत पुनः प्राप्त की। इसके विरुद्ध रु. 21.95 लाख का भुगतान लेखा शीर्ष 23/4700 आयोजनोत्तर के अंतर्गत प्राप्त कर दिया गया। जबकि ऐसे कार्य पर व्यय संबंधित संस्थाओं विनये कारण फलाई एश का जमाव डूबान क्षेत्र में हुआ, उनसे राशि प्राप्त कर डिपॉजिट भद्र में चलाविकाहियाँ की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना था और इस प्रकार प्राप्त की गई फलाई एश का सकारात्मक उपयोग करना था, किन्तु एनटीपीसी से कोल वेस्ट लाकर नहर के सर्वेस रोड में बिछाने पर रु. 9.34 लाख का व्यय किया। इस तरह आपने इस कार्य में अनावश्यक व्यय कर शासन को रु. 31.29 लाख की हानि पहुँचाई।



1-2 चलत नहर में सी सी लाइनिंग कार्य का ठेका निविदा के

माध्यम से दिनांक 2.1.2007 को कार्यदेश जारी कर कराया जा रहा था जिसमें नहर के सर्विस रोड में मुख्य बिजाने का कार्य भी सम्मिलित था। किंतु सर्विस रोड में मिट्टी एवं अन्य सामग्री सहित भरमार का कार्य, अन्य स्थानीय फर्मों को सौंपाई आदेश के स्वरूप में आदेश जारी कर रु. 11.987 लाख व्यय किया। इस प्रकार आपने रिटर्न केनाल के कार्य हेतु अनुबंधित ठेकेदार को अनधिकृत लाभ पहुँचाकर शासन को रु. 11.987 लाख की हानि पहुँचाई।

1-3

वरिष्ठ उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी के आतिथिक प्रभार के रूप में कार्य करते हुए आपका यह कर्तव्य बनता था कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से कठिनाई 1.1 एवं 1.2 में उल्लिखित कार्यों तथा इनसे संबंधित प्रावधानों को नियमानुसार नहीं होने बाबत संसूचित करते, एवं फिर भी निर्देश दिए जाने पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में जाए जाने की आपकी जिम्मेदारी बनती थी। परन्तु आपने ऐसा नहीं करते हुए अनियमित एवं अनधिकृत प्रावधानों के अन्तर्गत और स्वीकृति प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर अनियमितताएँ किया है।

1-4

उप संभाग में कार्यरत उप अभियंताओं के मध्य कार्य का आवंटन अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क्र. 2174/अवित 2006 दिनांक 31.10.2006 द्वारा किया गया था। किंतु उप अभियंताओं से कार्यावंटन के अनुक्रम कार्य न कराकर उनके आवंटित कार्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में भी अनियमित कार्य करने हेतु बाध्य किया।

1-5

आपके द्वारा विभिन्न फर्मों को 2322 सलाई आदेश के द्वारा किये गये कार्यों के बिना के माप दर्ज कर भुगतान किया गया, जबकि उक्त बिना के प्रदाय आदेशों में 152 आदेश छोड़कर शेष प्रदाय आदेश के कमांक एवं दिनांक उप संभागिय जावक पंजी में दर्ज नहीं है। इस प्रकार आपने मनगढ़त प्रदाय आदेश के कमांक दर्ज कर और उसको आधार



194. गणितीयक कर अधिनियम 1994 की धारा 35, 42 एवं

इस प्रकार आपने आयकर अधिनियम 1961 की धारा

राशि की अनाधिकृत सहायता प्रदान की।

लाख की राजस्व की हानि पहुँचाई तथा फर्मों का इतनी ही कर, अभिक्रयण पर में दर्शाए अनुसार शासन को रु. 7.94 प्रकार आपने उपरोक्त अधिनियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन स्वीत पर कर की वसूली अनिवार्य की जाती थी। इस एवं खनिज अधिनियम के तहत भुगतान की गई राशि से भुगतानों से आयकर अधिनियम, गणितीयक कर अधिनियम लाख से अधिक का भुगतान हुआ। नियमानुसार इन जारी किए जाते रहे, जिससे प्रत्येक फर्म को वर्ष में रु. 1 के अंतर्गत जारी कर प्रत्येक फर्म को वर्षभर लगातार आदेश रु. 5000/- के अंतर्गत तथा रु. 20000/- से 25000/- करके की जाती। कार्यों के आदेश सीधे स्थानीय फर्मों को दरों पर ठेकेदारों के भुगतान से स्वीत पर कर की वसूली आयकर, गणितीयक कर, एवं रायवटी की वसूली निर्धारित करण जाने के साथ-साथ अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत है। ठेके पर आवंटित कार्यों में अनुबंधित दरों पर कार्य रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्ति से भी वंचित किया आपने शासन को आयकर, गणितीयक कर, एवं रायवटी के आरोप क. 1 में उल्लिखित अनियमितता के फलस्वरूप

आरोप क-2

अंतर्गत अपने आपको दण्ड का भागी बना लिया है।

नियम 1966 के नियम 10 (तीन) एवं (सात) से (चौ) के है तथा छा सिविल सर्विसेस वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अधीन नियम 1965 के नियम - 3 के अनुसार गंभीर कदावरण किया नियम-9 का उल्लंघन कर, छा सिविल सर्विसेस आवरण नियम 2.075 (बी), छा वित्तीय संहिता भाग एक के इस प्रकार आपने कार्य विभाग नियमावलि भाग एक के

के भुगतान करने में आपकी अहम भूमिका रही।

अनाधिकृत रूप से जारी प्रदाय आदेशों के विरुद्ध प्राप्त बिना बनाकर बिना के माप दर्ज कर भुगतान किया। इस तरह



the charges are not correct. He also argues that there are no
Learned counsel for the petitioner argues that factually

विकासका वर्णन अभिकथन पर से दिया गया है ।

करके तथा करकर शासन को राजस्व की हानि भी कराई है,
की प्राप्ति होती । इस प्रकार आपने नियमों के विरुद्ध कार्य
पर वर्सुकी की जाती एवं लगभग रु. 0.20 लाख की राजस्व
रुका पद्धति से कार्य करने पर रोकेंदारों से करों की स्वीत
3 से वर्तित उत्तरदायित्वों का उत्तिव निवर्दन नहीं किया ।
कार्य विभाग नियमावलि भाग दो के अप्रैडिक्स 1.26 क. 1 एवं
रुको पर अनुबंध करा कर किए जाने थे । इस प्रकार आपने
सामान एवं कार्यों का भुगतान किया जाना पया गया जो
प्रति किया । उत्तरदायित्वी एवं इम्पेस्ट के माध्यम से ऐसे
करके अपने अधीनस्थ उप अभियंतों को भी ऐसा करने हेतु
से दी गई सीमा से अधिक का नगद भुगतान किया तथा ऐसा
अनुमति से ही की जा सकती थी । आपने इस तरह नियमों
अभियंता की तथा रु. 2500 तक अधीन अभियंता की
(सूची) के सं.क. 87 के अनुसार रु. 500 तक कार्यपालन
सीमा वितीय अधिकार प्रस्तिका 1995 (कार्य विभागों की
भुगतान हेतु निर्धारित सीमा केवल रु. 100 ही है । यह
विभाग नियमावलि भाग एक के नियम 4.067 के अनुसार नगद
से ले कर रु. 2500 तक के भुगतान करए जबकि कार्य
रु. 8.00 लाख का भुगतान किया । इन भुगतानों में रु. 500
अनिश्चित तरीके से सामग्री का कय एवं संभारण के कार्य में
उत्तरदायित्वी एवं इम्पेस्ट के माध्यम से अनियंत्रित एवं
आपने स्वयं एवं अपने अधीनस्थ उप अभियंतों से

आरोप क. - 3

भारी बना दिया है ।

वीन) एवं (सात) से (नौ) के अंतर्गत अपने आपको दण्ड का
वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अधीन नियम 1966 के नियम 10 (
संशोधन कदाचरण किया है तथा उग स्थित सर्वेक्षण
सर्वेक्षण आवरण नियम 1965 के नियम - 3 के अनुसार
संहिता भाग एक के नियम-9 का उल्लंघन कर, उग स्थित
खनिज अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ, उग वितीय



W.P(S)No.7088/2007

specific charges against the petitioner and it is only said in the charges that the petitioner was also indulged with the other authorities of the department for the alleged misconduct committed by them. He also argues that the charges were not issued to the petitioner within the stipulated period granted under rule 9 of M.P (C.G) Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1966.

I have heard learned counsel for the petitioner at length and have also gone through the documents filed alongwith Writ Petition.

In this case, as it appears from the documents, the petitioner was suspended on 14.8.2007 and the charge sheet was issued by the Government to him on 05.11.2007. Therefore, the charge sheet has been issued in time and no challenge can be made on this ground. As far as the grounds pertaining to the allegations in the charges are concerned those grounds are based on factual aspects of the matter and that cannot be enquired into by a writ court, which is absolutely a duty of the enquiring authority or the competent authority in this regard.

In the matter of **Union of India and others -vs- Upendra Singh (1994) 3 SCC 357**, the Apex Court has also held vide para 6 that in the case of charges framed in a disciplinary inquiry the tribunal or court can interfere only if on the charges framed (read with imputation or particulars of the charges, if any) no misconduct or other irregularity alleged can be said to have been made out or the charges framed are contrary to any law. At this stage, the tribunal has no jurisdiction to go into the correctness or truth of the charges. The tribunal cannot takeover the functions of the disciplinary authority. The truth or otherwise of the charges is a matter for the disciplinary authority to go into. Indeed, even after the conclusion of the disciplinary proceedings, if the matter comes to court or tribunal, they have no jurisdiction to look into the truth of the charges or into the correctness of the findings recorded by the disciplinary authority or the appellate authority as the case may be.

Admittedly, as stated above, the factual aspects of the matter are involved in this case and this Court cannot go into



the merits of the charges framed against the petitioner, at this stage, particularly with reference to their correctness etc.

For the foregoing discussion, I do not find any reason to interfere with the order of suspension or the charge sheet served upon the petitioner, at this stage.

The petition deserves to be and is accordingly dismissed at the motion stage itself.

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge

|Reo|